

प्रेषक,

एन0एस10नपलच्याल,

प्रमुख सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,

हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 09 अगस्त, 2006

विषय:- सीता देवी मैमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को शिक्षण कार्य हेतु ग्राम बिशनपुर झरड़ा जनपद हरिद्वार में कुल 2.141 है० भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सीता देवी मैमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी को शिक्षण कार्य हेतु राजस्व अनुभाग-1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या-558/16(1)/73-रा-1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या-1695/97-1-1 (60) 93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम बिशनपुर झरड़ा परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार के खसरा नं० 202 /1म क्षेत्रफल 0.456 है०, 202/2 क्षेत्रफल 0.456 है०, 203 /1 क्षेत्रफल 0.369 है०, 203 /2 क्षेत्रफल 0.491 है० तथा 203 /3 क्षेत्रफल 0.369 है० अर्थात् कुल क्षेत्रफल 2.141 है० भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना रू० 12,84,600.00 (रुपया बारह लाख चौरासी हजार छः सौ: मात्र) एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान नई दर पर निकाली गयी नालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया रू० 1,048.00 (रुपया एक हजार अड़तालीस) नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।
- (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा न्यास का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं0 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, सीता देवी मैमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, ईदगाह रोड, ज्वालापुर, हरिद्वार।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।